आकाशवाणी केन्द्र शिमला

29.08.2024 / प्रादेशिक समाचार / 18:00 बजे

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से प्रदेश में जितने भी स्कूल खुले हैं, उन्हें सरकार न तो बंद करेगी, न ही उनके नाम बदले जाएंगे। शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने आज सदन में विधायक विनोद कुमार और विपिन सिंह परमार द्वारा पूछे सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए ये बात कही। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार किसी भी स्कूल को लीज पर नहीं देगी और न ही उन्हें बेचेगी। मुख्मयंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने जो अटल आदर्श विद्यालय बनाने शुरू किए थे उनका काम जारी है और बजट की उपलब्धता के अनुसार इनके कार्य को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने तल्खी दिखाते हुए कहा कि पूर्व की जयराम सरकार के 5 सालों के कार्यकाल में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई और हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में 18वें स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता पर है और विपक्ष भी उनका इसमें साथ दे। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय में अच्छी शिक्षा मुहैया करवाई जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार शिक्षा के साथ हिमाचल के हितों को बेचने का प्रयास कर रही है।

प्रश्नकाल–2

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इनकार कर रहे हैं और स्कूल को लीज पर देने के विज्ञापन जारी हो चुके हैं। इस मुद्दे को लेकर फिर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया व नारेबाजी भी शुरू कर दी। साथ ही विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो गए। जयराम ठाकुर ने कहा कि पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय की जमीन को बेचा जा रहा है। अन्य गतिविधियों के लिए इस जमीन को दिया जा रहा है और स्कूलों को पट्टे पर देने की योजना है। इससे पहले, शिक्षा मंत्री की गैरमौजूदगी में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधायक विपिन परमार व विनोद कुमार के मूल सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में कुल 3 अटल आदर्श विद्यालय निर्माणाधीन हैं। इनके निर्माण के लिए 70 करोड़ की राशि आवंटित की है।

वाकआउट

प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज सदन में शराब के ठेकों की नीलामी का मामला गूंजा। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने प्रश्नकाल के दौरान नई शराब नीति में ठेकों के आवंटन का मामला उठाया और सरकार पर बड़े स्तर पर कथित भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगाया। वहीं, इस

मामले पर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तल्खी भी हुई और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन में नारेबाजी की और फिर सदन से वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि जब से उनकी सरकार सत्ता में आई है तब से सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। उन्होंने पूर्व की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब इनकी सरकार सत्ता में थी तो खजाने को लुटाया गया। इनके कार्यकाल में चार साल तक ठेकों को नीलामी नहीं की गई और सिर्फ लाइसेंस को रिन्यू किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के पांच साल के कार्यकाल में ठेकों से 6 सौ 65 करोड़ 42 लाख की आय हुई, जबकि कांग्रेस के एक साल के कार्यकाल में शराब के ठेकों की नीलामी से सरकार ने 4 सौ 85 करोड़ 18 लाख रुपए का राजस्व जुटाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब के ठेकों की नीलामी पूरी पारदर्शी तरीके से की गई है।

मुख्यमंत्री

प्रदेश में मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्यों, मुख्य संसदीय सचिवों और बोर्ड व निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के वेतन–भत्ते अगले दो महीने तक विलंबित होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए विधानसभा में आज इस संबंध में एक विशेष वक्तव्य दिया। उन्होंने विधायकों से भी स्वेच्छा से इसे दो माह के लिए विलंबित करने का आग्रह किया।

राज्यपाल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने युवाओं से पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया है। राज्यपाल ने आज चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्तमान ही बेहतर भविष्य का निर्माण करता है और युवा शक्ति स्वहित के साथ भारत की सनातन परम्परा को आत्मसात् कर सुखद् भविष्य की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि हरित आवरण में वृद्धि कर पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि नशा आज देश सहित समूचे विश्व की ज्वलंत समस्या बन कर उभरा है। राज्यपाल ने कहा कि नशे पर रोकथाम के लिए समाज को सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास गौरवमयी रहा है और हम सभी को देश के इतिहास से सीख लेकर विकास पथ पर अग्रसर होने की जरूरत है।

————————————————